भद्रेश बिपिनभाई सेठ

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1134-1135/2015)

1 सितंबर, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 438-अग्रिम जमानत-वर्ष 2001 में अपीलार्थी के खिलाफ केवल दर्ज किए गए बयान के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत बनाया गया आरोप-नौ साल बाद आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़ना-सत्र न्यायालय में कार्यवाही करने और अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए आदेश पारित किया गया-अपीलार्थी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन-सत्र न्यायाधीश द्वारा, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने का अनुदान-न्यायनिर्णयः केवल इसलिए कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप, जो एक गंभीर आरोप है, अब जोड़ा जाता है, अग्रिम जमानत के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है जब ऐसा आरोप बाद में जोड़ा जाता है और अभियोजन पक्ष की निष्क्रियता होती है।

जमानत-अग्रिम जमानत-अनुदान या इनकार-ध्यान में रखे जाने वाले कारक-बताए गए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 तत्काल मामले में, जहां बलात्कार के आरोप लगभग 17 साल पहले की अवधि से संबंधित हैं और जब वर्ष 2001 में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कोई आरोप नहीं बनाया गया था, और यहां तक कि अभियोजक ने भी लगभग 9 साल तक कोई कदम नहीं उठाया और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप केवल वर्ष 2014 में जोड़ा गया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप, जो एक गंभीर आरोप है, अब जोड़ा गया है, अग्रिम जमानत के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है जब इस तरह के आरोप को लंबे समय के बाद जोड़ा जाता है और अभियोजक की निष्क्रियता भी एक अंशदायी कारक है। [पैरा 17] [412-बी-सी]

1.2 मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को 17 साल पुरानी कथित घटना के संबंध में अग्रिम जमानत से इनकार करके, एक विचाराधीन के रूप में सलाखों के पीछे जाने के लिए मजबूर करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और जिसके लिए आरोप केवल वर्ष 2014 में तैयार किया गया है। जाँच पूरी हो चुकी है और ऐसा कोई आरोप नहीं है

कि अपीलार्थी न्याय के मार्ग से भाग सकता है। एफ. आई. आर. दर्ज की गई और मुकदमा वर्ष 2001 में शुरू हुआ; यद्यपि आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत बनाए गए आरोप के साथ, और इन सभी अवधियों के दौरान, अपीलार्थी ने कार्यवाही में भाग लिया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस अवधि के दौरान उसने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उक्त परिस्थितियों में, भले ही अपीलार्थी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाया गया हो, जब गणना किए गए अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जाती है तो यह अपने आप में अग्रिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं होना चाहिए। [पैरा 24] [421-जी-एच; 422-ए-सी]

1.3 विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। [पैरा ~ 7] [422-जी] गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 565:1980 (3) एस. सी. आर. 383-संदर्भित किया गया ।

सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2011) 1 एस. सी. सी. 694:10 (15) एस. सी. आर. 201-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

1980 (3) एस. सी. आर. 383	अनुसरण किया गया	पैरा 19

2010 (15) एस. सी. आर. 201 अनुसरण किया गया पैरा 22

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 1134-1135/2015

आपराधिक विविध आवेदन (जमानत रद्द करने के लिए) संख्या 9440/2013 आपराधिक विविध के साथ गुजरात के अहमदाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.07.2014 से। 2013 का आवेदन क्रमांक 15929

अपीलार्थी के लिए दुष्यंत दवे, हरिन रावल, अनिरुद्ध शर्मा, समर कछवाहा, नचिकेत दवे, राघवेंद्र एम. बजाज, आनंदो मुखर्जी, निपुर सक्सेना, प्रवीण कुमार होता।

प्रतिवादी की ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी, हेमन्तिका वाही, जेसल वाही, पूजा सिंह।

कोर्ट का फैसला जस्टिस एके सीकरी ने सुनाया:

1. अनुमति दी गयी।

2. अपीलार्थी, इन अपीलों में, अहमदाबाद शहर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए गुजरात में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.07.2014 के फैसले की वैधता को चुनौती देता है।

3. अपीलार्थी के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के संबंध में हुई एक लंबी घटना के तथ्यात्मक विवरण पर आने से पहले, हम संक्षिप्त तरीके से बताना चाहेंगे कि जिन परिस्थितियों में मामला इस न्यायालय में आया है।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 (इसके बाद 'अभियोजक' के रूप में संदर्भित) प्रासंगिक समय पर पड़ोसी थे और एक-दूसरे को जानते थे। 29.05.2001 पर, अभियोजक ने सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, गायकवाड़ हवेली, अहमदाबाद शहर को एक शिकायत लिखी जिसमें अपीलार्थी द्वारा कुछ समय के लिए उसके साथ किए गए उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उसमें अपीलार्थी के खिलाफ बलात्कार, भावनात्मक ब्लैकमेल और धमकियों के आरोप लगाए गए थे। दो दिनों के बाद यानी 31.05.2001 पर, संबंधित पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने फिर से दुर्व्यवहार, ब्लैकमेल आदि के आरोप लगाए। हालाँकि, उसके इस बयान में, जो जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा दर्ज किया गया था, बलात्कार के आरोप स्पष्ट रूप से गायब थे। 31.05.2001 पर दिए गए बयान के आधार पर, एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था और वर्ष 2001 में भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 506 (2) के तहत आरोप तय किया गया था। अपीलार्थी को उक्त मामले में जमानत पर स्वीकार कर लिया गया था। मुकदमा चल रहा है जो कई वर्षों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। वर्ष 2010 में, अभियोजक ने

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत भी आरोप जोड़ने के लिए आवेदन किया। महानगर दंडाधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता की मुख्य जांच के बाद ही उक्त आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। अभियोजक ने अहमदाबाद में सिटी सेशन जज की अदालत के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी। मामले को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया कि दोनों पक्षों को मौका देने के बाद आवेदन पर पूरी तरह से नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। 31.03.2012 पर, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 173 (8) के तहत विशेष जांच करने का निर्देश दिया। संतुष्ट नहीं होने के कारण, पक्षों ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। निर्देश जारी किए गए थे। अंततः, पुलिस ने एक संशोधित आरोप पत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला भी बनाया गया था। आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़ने के मद्देनजर, मजिस्ट्रेट ने सत्र न्यायालय में कार्यवाही करने और अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए आदेश पारित किया। हालाँकि, अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए इस आदेश के निष्पादन पर 07.05.2013 तक रोक लगा दी गई थी। इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत देने के लिए अहमदाबाद में सिटी सेशन कोर्ट संख्या 16 का रुख किया, जिसे अंततः 18.05.2013 पर मंजूर कर लिया गया। अग्रिम जमानत देने के इस आदेश के खिलाफ,

अभियोजक ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने वाले दिनांक 18.07.2014 के विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह इस आदेश का औचित्य और वैधता है जो तत्काल अपीलों में हमारे सामने विचाराधीन है।

4. उपरोक्त संक्षिप्त विवरण में दर्शाया गया है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप शुरू में वर्ष 2001 में केवल आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत तैयार किया गया था। जहां तक आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप का संबंध है, इसे केवल वर्ष 2014 में जोड़ा गया है। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत मूल आरोप 31.05.2001 पर दर्ज बयान के आधार पर तैयार किया गया था जिसे एफ. आई. आर. माना गया था और जिसमें बलात्कार का आरोप नहीं था। यदि किसी को इन तथ्यों को देखना है, इस तथ्य के साथ कि बलात्कार का आरोप वर्ष 1997-98 का है, तो अग्रिम जमानत देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश में कोई गलती नहीं मिल सकती है। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया जाता है, मामले को इतने सरल तरीके से नहीं लेता है और इसलिए, इस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा अनिवार्य हो गई है।

5. उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया जिनके कारण देर से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़े गए। इस प्रकार, उन विस्तृत घटनाओं का जायजा लेना और उसके बाद यह तय करना आवश्यक होगा कि उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ है या नहीं। इन तथ्यों को विस्तार के साथ दोहराया गया है जो हमारे उद्देश्यों के लिए बिल्कुल आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बयान के आधार पर 31.05.2001 पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले, अभियोजक ने 29.05.2001 पर सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में, उसने कहा कि वह एक गृहिणी है और डेढ़ साल से 1, नवपद टेनमेंट, नव विकास गृह के सामने, ओपेरा के पीछे रह रही थी। उसने आगे उल्लेख किया कि इस स्थान पर जाने से पहले, वह 10 साल से साणंद में अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। वह शादीशुदा थीं, उनके तीन बच्चे थे, और उनके पति एक ज्वैलर थे। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि उससे लगभग ढाई या तीन साल पहले वह सी. एन. विद्यालय गई थी जहाँ उसकी बेटी देवल पढ़ रही थी। घर लौटने के लिए उसे बस पकड़नी थी। जब वह बस स्टैंड पर खड़ी थी, तो अपीलकर्ता, जो उसका पड़ोसी था, अपनी कार में उस जगह से गुजरा और अभियोजक को देखकर उसने उसे कार में बैठने के लिए कहा क्योंकि वह भी घर जा रहा था। हालाँकि, उसने शुरू में मना कर दिया, लेकिन

उसके बाद वह उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों से अनजान होकर कार में बैठ गई। इसके बाद, वह कार को तेलव गांव के पास किसी निर्जन स्थान पर ले गया, उसकी पिटाई की और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसने उसे उपरोक्त घटना किसी को न बताने की धमकी भी दी। इन धमकियों से डरकर उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, एक महीने के बाद उसने यह धमकी देते हुए बलात्कार का कृत्य दोहराया कि अगर अभियोजक सहमत नहीं हुआ तो वह उसके पति और अन्य लोगों को बताएगा। वह उसे होटल एलिस टाउन ले गया और उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद, उसने उसे यह कहते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी कि उसने उसकी तस्वीरें खींची हैं। इस तरह उन्होंने अभियोजक के साथ संबंध बनाए रखा। इस शिकायत में आगे कहा गया है कि वह अहमदाबाद चली गई लेकिन अहमदाबाद आने के बाद भी, उसने उस चरण को बदनाम करने की धमकी के साथ पत्र भेजना शुरू कर दिया, उसने अपने पति और ससुराल वालों को बताया। वह एक गैर सरकारी संगठन, ज्योति संघ के पास गई और उनके समर्थन से प्रोत्साहित होकर, उसने अपीलार्थी की ओर से लगातार उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई।

7. 31.05.2001 पर, जाँच अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में उसका बयान दर्ज किया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप निहित हैं और पूरा बयान निम्नानुसार हैः

"वादी मनीषाबेन आदेश देती है कि हालाँकि प्रतिवादी भद्रेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन आज तक उसे आरोपित नहीं किया गया है। हमारी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। इन दो दिनों में, भद्रेश हमारी पहुंच के दौरान भयानक चेहरा बना रहा है और अपमानजनक और गंदा व्यवहार कर रहा है। कल रात के समय लगभग 8.15 बजे भद्रेश की माँ बहुत जोर से इस तरह से बोल रही थी कि मुझे वही सुनाई दे रहा है क्योंकि वे हमारे सामने रह रहे हैं कि हम भरण-पोषण का भुगतान करेंगे और भद्रेश खुद इस तरह से बोल रहा था और मुझे अपनी कनीज के रूप मे रहने को बोल रहा था।वह मेरे घर के सामने व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंस रहा है और वह मेरे पति के साथ भी अपमानजनक तरीके से व्यवहार कर रहा है जिसे न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही खुलासा किया जा सकता है। इस समय जब हम साणंद से अहमदाबाद आने के लिए निकले तो भद्रेश का कर्मचारी हमारा पीछा कर रहा था और लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक हमारे पीछे था और मुझे नहीं पता कि उसका कोई और साथी था या नहीं, लेकिन उसके साथी मेरे चारों ओर इस तरह से मौजूद हैं कि वह हमारा पीछा कर रहा था, भले ही मैं या मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे थे। अब, मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है जो बड़ी हो रही है और जवान हो रही है क्योंकि भद्रेश भी उसे बुरे इरादे से देख रहा है। उसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है।

मैंने उपरोक्त कथन को मन की पूर्ण स्वस्थ स्थिति में और बिना किसी अनुचित दबाव के लिखा है।

मेरे सामने हस्ताक्षर मनीष के मेहता

वंदना पटवाः 31.05.2001

31.05.2001 "

8. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, पुलिस ने ज्योति संघ के परामर्शदाताओं के बयान दर्ज किए, जिन्होंने पुष्टि की कि अभियोजक ने अपीलार्थी द्वारा कथित बलात्कार के संबंध में उन्हें बयान दिया था। जो भी हो, प्राथमिकी केवल आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत 31.05.2001 पर दर्ज की गई थी, जिसमें सी. आर. नं. II. 3009/2001 और उस आधार पर, शुल्क केवल 25.06.2001 पर उपरोक्त धारा के तहत तैयार किया गया था। इसके अलावा किसी न किसी कारण से, उक्त आरोप के तहत भी अभियोजन पक्ष के मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

9. 07.12.2010 पर, अभियोजक द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध को शामिल करने के साथ-साथ 29.05.2001 की शिकायत के आधार पर आरोप में संशोधन करने और उसे एफ़. आई. आर. के रूप में मानने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। प्रारंभ में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस अनुरोध से सहमत नहीं थे और इस आशय का आदेश पारित किया कि जब तक अभियोजक की जाँच-इन-चीफ दर्ज नहीं

की जाती, तब तक आरोप में संशोधन/परिवर्तन करना उचित नहीं था। हालांकि, उस आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका में, सत्र अदालत ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया। रिमांड के बाद आदेश दिनांक 31 पर जारी किया गया।31.03. 2012 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच का निर्देश देते हुए पारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि इस तरह के आरोप तैयार करने की आवश्यकता पुलिस द्वारा की गई जांच पर निर्भर करेगी। विवरण बताए बिना, यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि मामले को सभी पक्षों द्वारा सत्र न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। इसके बाद, अभियोजक एसएलपी (आपराधिक) संख्या 636/2013 के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.10.2012 के आदेश के खिलाफ इस अदालत में आया, जिसने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने पहले ही आगे की जांच का आदेश दे दिया था। उक्त एसएलपी (आपराधिक) संख्या 636/2013 को इस तथ्य पर ध्यान देते हुए 04.02.2013 पर निपटाया गया था कि हालांकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ 31.03.2012 पर पुलिस द्वारा आगे की जांच का आदेश दिया था, लेकिन उस तारीख तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। उस आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

"हमें सूचित किया जाता है कि आज तक पुलिस ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। यदि ऐसा है, तो हम पुलिस की निष्क्रियता पर आश्चर्य और पीड़ा दोनों महसूस करते हैं और हम मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित 2011 के आपराधिक मामला संख्या 51 के जांच अधिकारी को निर्देश देते हैं, और उनके समक्ष इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/पेश करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त निर्देश को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अब इस विशेष अनुमति याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहता है। इसे बिना किसी दबाव के खारिज कर दिया जाता है।

10. इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी की और रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 जोड़कर आरोप पत्र दायर किया और उस आधार पर, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 25.04.2013 पर एक आदेश पारित किया गया, जिससे मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और आगे निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में लिया जाए, जमानत बांड को रद्द कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी ने उक्त सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया जो 18.05.2013 पर दिया गया था।

जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत देने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

11. श्री दुष्यंत दवे और श्री हरिन रावल, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें अभिलेख पर मौजूद सामग्री के माध्यम से ले गए, जिसके आधार पर यह तर्क देने की मांग की गई थी कि अपीलार्थी और अभियोजक के बीच परिचय था और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि शारीरिक संबंध, यदि कोई हो, सहमति से था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आई. ओ. के समक्ष 31.05.2001 पर दर्ज किए गए उसके बयान में बलात्कार का कोई आरोप नहीं थाः भले ही आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत आरोप तैयार किया गया था, अभियोजक ने उक्त आरोप सरलीकरणकर्ता को तैयार करने पर आपत्ति नहीं जताई या आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत भी आरोप जोड़ने पर जोर नहीं दिया; आरोप तय होने के 9 साल से अधिक के अंतराल के बाद, इस उद्देश्य के लिए आवेदन दायर किया गया था; 10 द्वारा दायर नए आरोप पत्र में, 10 ने स्पष्ट रूप से कहा कि बलात्कार के संबंध में कोई अन्य परिस्थितिजन्य सबूत एकत्र नहीं किया जा सकता है जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा उसके बयान के अलावा आरोप लगाया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजक द्वारा दी गई शिकायत के अंत में ज्योति संघ, गैर सरकारी संगठन को की गई शिकायत में एक टिप्पणी थी कि उक्त

शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पक्ष सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। नोट इस प्रकार हैः

"इस मामले की फाइल को लंबित रखा जाए और जब भी हम चाहें, तभी आप इस मामले को फिर से लड़ें और यह उन दोनों की इच्छा है कि इस मामले को लंबित रखा जाए।"

मेरे सामने हस्ताक्षर मनीष के मेहता

वंदना पटवाः 29.03.2001

29.03.2001

यह भी बताया गया कि 2001 और 2010 के बीच, अभियोजक अपना बयान देते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि, उक्त एनजीओ में वकील वंदना पटवा का बयान दर्ज किया गया था। श्री डेव ने उक्त गवाह से जिरह का उल्लेख किया जिसमें इस गवाह ने स्वीकार किया था कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 31.05.2001 के बयान में बलात्कार के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया था। यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि बलात्कार की घटना किस स्थान पर और किस समय हुई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत देना सही माना। जमानत रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कारणों पर विद्वान वकील द्वारा टिप्पणी की गई थी कि वे रिकॉर्ड पर आधारित नहीं हैं,

विशेष रूप से, उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कि अभियोजक को अपनी शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज कराने के लिए और विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़ने के लिए मैराथन दौड़ना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया कि सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए उचित कारण बताने में विफल रहा है। यह इंगित किया गया कि अभियोजक के पति के खिलाफ आपराधिक मामले दायर करने में अपीलार्थी की ओर से उठाए गए कदम, जिसमें अभियोजक के पति को बरी कर दिया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों को परेशान करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ के रूप में माना जाता है और उस आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि अपीलार्थी अग्रिम जमानत के लाभ का हकदार नहीं था। इस ओर से प्रस्तुतिकरण यह था कि भले ही अभियोजक द्वारा अभियोजक के पति के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत या मामले झूठे माने जाते हैं, उनका तत्काल मामले से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, अपीलार्थी की ओर से इस तरह के कार्यों को कभी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के रूप में नहीं माना जा सकता है।

12 अभियोजक व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ और उसके मामले में बहस की। उन्होंने वर्तमान कार्यवाही के विरोध में उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के माध्यम से हमें व्यापक रूप से लिया, जिसके आधार पर उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दियाः

(क) अभियोजक को अपीलार्थी द्वारा परेशान किया गया था। संभोग का पहला कार्य उसकी इच्छाओं के खिलाफ था और स्पष्ट रूप से एक बलात्कार था। इस बलात्कार को अंजाम देने के बाद, अपीलार्थी ने उसे धमकी दी और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस आधार पर, उसने अभियोजक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जिसमें उसे रखा गया था और उसकी इच्छाओं के खिलाफ संभोग के बाद के कृत्य किए जो आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध करने के अलावा और कुछ नहीं थे।

(ख) अपीलार्थी द्वारा न केवल अभियोजक को बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी विभिन्न पत्र लिखे गए थे, जो अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति उसके निरंतर उत्पीड़न को दर्शाते हैं।

(ग) अपीलार्थी की अभियोजक की बेटी पर भी बुरी नजर थी, जो बढ़ती उम्र की थी और इस संबंध में भी अभियोजक को ब्लैकमेल करना चाहती थी।

(घ) अभियोजक को परेशान करने के लिए, अपीलार्थी ने अभियोजक के पति पर झूठे मामले भी लगाए ताकि अभियोजक पर मामले को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके।

ई) उसने यह भी कहा कि न केवल 19.03.2001 को ज्योति संघ को की गई शिकायत में उसने बलात्कार के आरोप लगाए थे, बल्कि 29.05.2001 को एसीपी को दी गई उसकी शिकायत में भी ऐसे आरोप लगाए गए थे।

उनके अनुसार, वास्तव में, जांच अधिकारी द्वारा 31.05.2001 को जो बयान दर्ज किया गया था, वह सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था, जिसने जानबूझकर अपीलकर्ता द्वारा उसके बलात्कार के संबंध में अपना बयान छोड़ दिया, हालांकि विशेष रूप से कहा गया था। यही कारण है कि उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप शामिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट में इस प्रार्थना के साथ आवेदन दायर करना पड़ा कि एसीपी के समक्ष दिनांक 29.05.2001 की शिकायत को एफआईआर माना जाना चाहिए, न कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज 31.05.2001 का बयान।

(च) उसने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध का आरोप लगाने के लिए उसे इस अदालत में आना होगा।

13. राज्य की ओर से पेश वकील सुश्री हेमंतिका वाही ने अभियोजक की याचिका का समर्थन किया। उनका निवेदन था कि एक बार आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़ा गया है जो एक गंभीर आरोप था और अपराध गैर-जमानती होने के कारण, कार्रवाई का उचित तरीका अपीलार्थी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश देना था। उनका निवेदन था कि इस आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह अग्रिम जमानत का मामला नहीं था।

14. हमने आरोपों पर उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक और गंभीरता से विचार किया है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ बलात्कार का आरोप है और अभियोजक द्वारा पेश किया गया मामला यह है कि एक असहाय और कमजोर आत्मा के रूप में, उसे अपीलार्थी द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित, शारीरिक शोषण और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।

15. सबसे पहले, यह याद दिलाना आवश्यक है कि वर्तमान कार्यवाही में, यह न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप तैयार करने की व्यवहार्यता या उसके गुण-दोष के बारे में नहीं बल्कि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देने के बारे में चिंतित है। इसलिए, अभियोजक की दलीलें कि इस तरह का आरोप सही तरीके से तैयार किया गया है और अपीलार्थी की ओर से अभियोजन मामले में खामियों और कमजोरियों को खोजने का प्रयास करना, शामिल मुद्दे के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं होगा। इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या अपीलार्थी और अभियोजक के बीच कोई शारीरिक संबंध था और यदि ऐसा है, तो क्या यह सहमति से था और इसलिए, बलात्कार का कोई आरोप नहीं बनाया गया था। तथ्य यह है कि बलात्कार का आरोप तय किया गया है। अंततः यह विचारण न्यायालय पर होगा कि वह इस आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचे कि क्या ऐसा आरोप साबित होता है या नहीं। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के

साथ, हम मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात्, क्या इस मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी अग्रिम जमानत का हकदार था या नहीं और क्या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत को रद्द करने में उचित था।

16. इस प्रयोजन के लिए, हम सबसे पहले स्वीकृत स्थिति पर प्रकाश डालेंगे जो इस प्रकार है:

बलात्कार के आरोप 1997-1998 के हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक द्वारा एनजीओ ज्योति संघ को दिए गए दिनांकित 19.03.2001 के बयान में, उसने बलात्कार के आरोप लगाए थे। समान रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने 29.05.2001 पर भी एसीपी को अपनी शिकायत में इन आरोपों को दोहराया था। हालाँकि, कुछ जिज्ञासु कारणों से, जाँच अधिकारी द्वारा 31.05.2001 पर दर्ज किए गए उसके बयान में बलात्कार के आरोपों का उल्लेख नहीं मिला, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जांच अधिकारी ने बयान को सही ढंग से दर्ज नहीं किया और जानबूझकर बलात्कार के आरोपों के बारे में उल्लेख करना छोड़ दिया। वास्तव में, क्या ऐसा हुआ, यह मुकदमे के दौरान तय किया जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि जब प्राथमिकी 31.05.2001 पर दर्ज बयान के आधार पर दर्ज की गई थी और आरोप पत्र केवल आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए दायर किया गया था,

तो अभियोजक ने उस समय कुछ नहीं कहा था। जब संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा केवल आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत आरोप तय किया गया था तब भी कोई विरोध नहीं हुआ था। इस संबंध में पहली बार वर्ष 2008 में आपत्ति उठाई गई थी, यानी आरोप तय होने के लगभग 7 साल बाद और वर्ष 2010 में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप शामिल करने के लिए आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि ए. सी. पी. को दी गई उनकी शिकायत को एफ. आई. आर. के रूप में माना जाए। अभियोजक के पास इस देरी के लिए वैध कारण हो सकते हैं। हालाँकि, इस स्तर पर हमें इसमें नहीं जाना है क्योंकि यह फिर से मुकदमे का विषय है और यह सत्र न्यायालय को अंततः यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस तरह की देरी को उपयुक्त रूप से समझाया गया था और/या आरोप के गुण-दोष पर इसका कोई प्रभाव है। यह दोहराया जाता है कि हमें केवल अग्रिम जमानत देने की व्यवहार्यता के सवाल पर फैसला करना है ।

17. इस तरह के मामले में जहां बलात्कार के आरोप लगभग 17 साल पहले की अवधि से संबंधित हैं और जब वर्ष 2001 में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत कोई आरोप नहीं बनाया गया था, और यहां तक कि अभियोजक ने भी लगभग 9 साल तक कोई कदम नहीं उठाया और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप केवल वर्ष 2014 में जोड़ा गया है, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि आई. पी. सी.

की धारा 376 के तहत आरोप, जो एक गंभीर आरोप है, अब जोड़ा गया है, अग्रिम जमानत के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है जब इस तरह के आरोप को लंबे समय के बाद जोड़ा जाता है और अभियोजक की निष्क्रियता भी एक अंशदायी कारक है।

18. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज कराने के लिए और विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोप जोड़ने के लिए मैराथन दौड़ना पड़ा। हमने ऊपर जो उल्लेख किया है, उसे देखते हुए ये अवलोकन सही नहीं हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी गलत उल्लेख किया है कि सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने के लिए उचित कारण नहीं बताए हैं। वास्तव में, जिन कारणों ने हमें राजी किया है और ऊपर दर्ज किए गए हैं, वे ठीक वही कारण हैं जो सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देते समय दिए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी गलत टिप्पणी की है कि यह अपीलकर्ता ही है जो उचित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज होने से पहले मामले को एक दशक तक खींचने में सक्षम था। मामले का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के इस अवलोकन का समर्थन नहीं करता है। जहाँ तक अभियोजक के पति के खिलाफ झूठी शिकायतें और मामले दर्ज करने में अपीलार्थी के आचरण पर टिप्पणी करने वाले विवादित आदेश में चर्चा का संबंध है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विरोधाभासी टिप्पणी की है। एक स्थान पर, अपीलार्थी की ओर से इस

तरह के कदम की गवाह को परेशान करने के रूप में निंदा की जाती है और इसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के रूप में माना जाता है। हालांकि, एक अन्य स्थान पर, उच्च न्यायालय ने स्वयं टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता या अभियोजक इस आधार पर अग्रिम जमानत रद्द नहीं करवा सकते हैं और इसके अनुदान के बाद जमानत के आदेश का दुरुपयोग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अनुसार, सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने का आदेश स्वयं अनुचित था और यह सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का आधार है।

19. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अग्रिम जमानत देने से संबंधित कानून पर चर्चा करना चाहेंगे जैसा कि न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय एक ऐसा निर्णय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मामले में संविधान पीठ ने जोर देकर कहा कि संहिता की धारा 438 में निहित अग्रिम जमानत के प्रावधान की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत की गई है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसलिए, इस तरह के प्रावधान में संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में संहिता की धारा 438 की उदार व्याख्या की आवश्यकता है। संहिता बताती है कि अग्रिम जमानत एक गिरफ्तारी-पूर्व कानूनी प्रक्रिया है जो निर्देश देती है कि यदि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में यह जारी किया जाता है, उसके बाद

उस आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है जिसके संबंध में निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जमानत के एक सामान्य आदेश और अग्रिम जमानत के आदेश के बीच अंतर यह है कि जबकि पूर्व को गिरफ्तारी के बाद दिया जाता है और इसलिए इसका अर्थ पुलिस की हिरासत से रिहाई है, बाद वाला गिरफ्तारी की प्रत्याशा में दिया जाता है और इसलिए गिरफ्तारी के समय ही प्रभावी होता है। इसलिए धारा 438 के तहत एक निर्देश का उद्देश्य संहिता की धारा 46 द्वारा विचारित 'स्पर्श' या कारावास से सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इस प्रावधान का सार निम्नलिखित तरीके से सामने लाया गया हैः

"26. हम श्री तारकुंडे के निवेदन में बहुत सार पाते हैं कि चूंकि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, इसलिए अदालत को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ झुकना चाहिए, विशेष रूप से जब उस धारा के संदर्भ में विधायिका द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो निर्दोष होने के अनुमान का लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह अग्रिम जमानत के लिए अपने आवेदन की तारीख को उस अपराध के लिए दोषी नहीं है, जिसके संबंध में वह जमानत मांगता है। बाधाओं और शर्तों का अत्यधिक उदार निवेश जो धारा 438 में नहीं पाए जाते हैं, इसके प्रावधानों को संवैधानिक रूप से कमजोर बना सकता है

क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि हटा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248 के निर्णय के बाद, कि संविधान के अनुच्छेद 21 की चुनौती का सामना करने के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। धारा 438, जिस रूप में विधायिका द्वारा इसकी कल्पना की गई है, इस आधार पर कोई अपवाद नहीं है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करती है जो अन्यायपूर्ण या अनुचित है। हमें, किसी भी कीमत पर, उसमें पाए जाने वाले शब्दों को पढ़कर इसे एक संवैधानिक चुनौती के लिए खुला छोड़ने से बचना चाहिए।

20. यद्यपि न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सामान्य जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अग्रिम जमानत के अधिकार के सटीक समानांतर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, फिर भी ऐसे सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्, जमानत का उद्देश्य जो मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, और इस प्रश्न के समाधान में लागू किया जाने वाला उचित परीक्षण कि क्या जमानत दी जानी चाहिए या अस्वीकार की जानी चाहिए, यह है कि क्या यह संभव है कि पक्षकार अपना मुकदमा चलाते हुए दिखाई देगा। अन्यथा, जमानत को

सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने आदि की कोई संभावना है। एक बार जब ये परीक्षण संतुष्ट हो जाते हैं, तो एक विचाराधीन व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए, जो एक अन्य कोण से देखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, अर्थात्, एक आरोपी व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता प्राप्त है, वह अपने मामले की देखभाल करने और अपना बचाव करने के लिए हिरासत में होने की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। इस प्रकार, जमानत की मंजूरी या गैर-मंजूरी विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इसका संचयी प्रभाव न्यायिक निर्णय में प्रवेश करता है। न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि किसी भी एक परिस्थिति को सार्वभौमिक वैधता के रूप में या जमानत देने या अस्वीकार करने को आवश्यक रूप से उचित ठहराने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने अग्रिम जमानत के निष्कर्षों पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा कीः

"31. अग्रिम जमानत के संबंध में, यदि प्रस्तावित आरोप न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी गुप्त उद्देश्य से प्रतीत होता है, तो उद्देश्य आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाना और अपमानित करना है, तो आम तौर पर उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर आवेदक को रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा। दूसरी ओर, यदि यह संभावना प्रतीत होती है कि आवेदक की पूर्ववृत्तियों पर विचार

करते हुए, कि अग्रिम जमानत के आदेश का लाभ उठाते हुए वह न्याय से भाग जाएगा, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन प्रस्तावों का विपरीत आवश्यक रूप से सच नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि यह एक अक्षम्य नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रस्तावित आरोप दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत न हो; और समान रूप से, यदि कोई डर नहीं है कि आवेदक फरार हो जाएगा तो अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। कई अन्य विचार भी हैं, जिनका वर्णन करना बहुत कठिन है, जिनके संयुक्त प्रभाव को अदालत को अग्रिम जमानत देते या अस्वीकार करते समय ध्यान देना चाहिए। प्रस्तावित आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, उन घटनाओं का संदर्भ जिनके कारण आरोप लगाए जाने की संभावना है, मुकदमे में आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने की एक उचित संभावना, एक उचित आशंका कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और "जनता या राज्य के व्यापक हित" कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें अदालत को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन विचारों की प्रासंगिकता को राज्य बनाम कैप्टन जगजीत सिंह, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 253: (1962) 3 एस. सी. आर. 622: (1962) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 216 में इंगित किया गया था, जो हालांकि, पुरानी धारा 498 के तहत एक मामला था जो संहिता की वर्तमान धारा 439 से मेल खाती है। यह याद रखना सर्वोपरि है कि व्यक्ति की

स्वतंत्रता समाज के अस्तित्व के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी व्यक्ति के अहंकारी उद्देश्यों के लिए। अग्रिम जमानत मांगने वाला व्यक्ति अभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो निर्दोष होने के अनुमान का हकदार है। वह अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, उन शर्तों को स्वीकार करके जो अदालत इस आश्वासन पर विचार करते हुए लागू करना उचित समझती है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

21. यह ध्यान देने योग्य है कि संहिता की धारा 438 (1) में आने वाली "हो सकता है, यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय, न्यायालय ने इंगित किया कि वह न्यायालय को किसी विशेष मामले में शक्ति का प्रयोग करने या न करने का विवेकाधिकार देता है, और एक बार ऐसा विवेकाधिकार केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो स्वयं अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है यदि परिस्थितियां अन्यथा उचित हैं। साथ ही, यह भी आवेदक का दायित्व है कि वह अग्रिम जमानत देने के लिए मामला बनाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे एक "विशेष मामला" बनाना होगा। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायिक शक्ति का एक बुद्धिमान प्रयोग अनिवार्य रूप से उन बुरे परिणामों का ध्यान रखता है जो इसके असंयमित उपयोग से निकलने की संभावना है।

22. एक अन्य मामला जिसे हम संदर्भित करना चाहते हैं, वह है सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय। यह मामला संहिता की धारा 438 की एक विस्तृत टिप्पणी देता है, जिसमें लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया गया है और इस प्रक्रिया में यह गुरबख्श सिंह के मामले में उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले पर निर्भर करता है। पहले पैरा में, न्यायालय ने परस्पर विरोधी हितों पर प्रकाश डाला, जिन्हें यह निर्णय लेते समय संतुलित किया जाना चाहिए कि जमानत दी जानी है या नहीं, जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट हैः

"1. अनुमति दी गई। इस अपील में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के महत्व से संबंधित महान सार्वजनिक महत्व के मुद्दे शामिल हैं। जमानत देने या अस्वीकार करने में समाज की महत्वपूर्ण रुचि है क्योंकि प्रत्येक आपराधिक अपराध राज्य के खिलाफ अपराध है। जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश को परस्पर विरोधी हितों, अर्थात् व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता और समाज के हित के बीच पूर्ण संतुलन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जमानत का कानून दो परस्पर विरोधी हितों को जोड़ता है, अर्थात्, एक ओर, अपराध करने वालों के खतरों और जमानत पर रहते हुए एक ही अपराध को दोहराने की क्षमता से समाज को बचाने की आवश्यकताएं और दूसरी ओर, एक आरोपी के निर्दोष होने की धारणा के संबंध में आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत

का पूर्ण पालन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता।

23. तत्काल मामले के प्रयोजनों के लिए जिन सिद्धांतों को हटाया जा सकता है, उन्हें निम्नानुसार बताया जा सकता है:

(i) अभियुक्त के खिलाफ दायर शिकायत की पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है, जिसमें यह पहलू भी शामिल है कि क्या शिकायतकर्ता ने पहले के अवसर पर झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज की है। अदालत को इस तथ्य की भी जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कोई पारिवारिक विवाद है और शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यदि शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी के बीच मिलीभगत स्थापित हो जाती है तो जांच अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(ii) आरोप की गंभीरता और अभियुक्त की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को उन वैध कारणों को दर्ज करना चाहिए जिनके कारण आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। असाधारण मामलों में, गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारणों को दर्ज किया जा सकता है, ताकि जमानत आवेदन पर विचार करते

समय, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की टिप्पणियों और टिप्पणियों का भी अदालत द्वारा उचित मूल्यांकन किया जा सके।

(iii) न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करें। जमानत देने के विवेकाधिकार का उपयोग उपलब्ध सामग्री और विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां अदालत का विचार है कि आरोपी जांच में शामिल हो गया है और वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है, उस स्थिति में हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए। गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी बदनामी, बदनामी और अपमान जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी से न केवल अभियुक्त के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए और कभी-कभी पूरे समुदाय के लिए कई गंभीर परिणाम होते हैं। अधिकांश लोग दोषसिद्धि से पहले या दोषसिद्धि के बाद गिरफ्तारी के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में उल्लिखित सीमाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। धारा 438 की प्रचुरता को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभियुक्त को एक "विशेष मामला" बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वस्तुतः, धारा 438 सी. आर. पी. सी. द्वारा प्रदत्त हितकारी शक्ति को एक मृत पत्र में बदल देता

है। अग्रिम जमानत मांगने वाला व्यक्ति अभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो निर्दोष होने के अनुमान का हकदार है। वह अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उन शर्तों को स्वीकार करके जो अदालत इस आश्वासन पर विचार करते हुए लागू करने के लिए उचित समझती है कि यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

(v) अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर कार्रवाई का उचित तरीका यह होना चाहिए कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध कथनों और आरोपों का मूल्यांकन करने के बाद यदि अदालत अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है तो अंतरिम जमानत दी जाए और लोक अभियोजक को नोटिस जारी किया जाए। लोक अभियोजक को सुनने के बाद अदालत या तो अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर सकती है या जमानत देने के प्रारंभिक आदेश की पुष्टि कर सकती है। अदालत निश्चित रूप से अग्रिम जमानत देने के लिए शर्तें लगाने का हकदार होगा। यदि अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है तो लोक अभियोजक या शिकायतकर्ता किसी भी समय अग्रिम जमानत की शर्तों को रद्द करने या संशोधित करने के लिए उसी अदालत का रुख करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को आम तौर पर मामले की सुनवाई तक जारी रखा जाना चाहिए।

(vi) यह एक तय कानूनी स्थिति है कि जमानत देने वाली अदालत को भी इसे रद्द करने की शक्ति है। जमानत देने या रद्द करने के विवेकाधिकार का उपयोग किसी भी समय नई सामग्री या परिस्थितियों का पता लगाने पर आरोपी, लोक अभियोजक या शिकायतकर्ता के कहने पर किया जा सकता है।

(vii) सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, एक बार जब अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो अभियुक्त को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना और फिर से नियमित जमानत के लिए आवेदन करना अनुचित होगा।

(viii) सभी मामलों में न्यायालय में निहित विवेक का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जो इसके प्रयोग को उचित ठहराने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अदालत के विवेक का भी सावधानी और विवेक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे आगे की यात्रा करना और विधायिका द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्ति और विवेक को स्व-लागू सीमाओं की कठोर संहिता के अधीन करना अनावश्यक है।

(ix) अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कोई लचीले दिशानिर्देश या स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि

अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए भविष्य की सभी परिस्थितियों और स्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। विधायी इरादे के अनुरूप, अग्रिम जमानत की मंजूरी या अस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए।

(x) हम उस निर्णय के पैरा 112 को भी पुनः प्रस्तुत करेंगे जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित कारकों और मापदंडों को चित्रित किया है जिन्हें अग्रिम जमानत पर विचार करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता हैः

(क) गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता और अभियुक्त की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए।

(ख) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या अभियुक्त ने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास का सामना किया है;

(ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(डी) आरोपी के दोबारा ऐसा करने की संभावना समान या अन्य अपराध;

(ई) जहाँ आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं;

(च) विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों में अग्रिम जमानत देने का प्रभाव;

(छ) अदालतों को अभियुक्त के खिलाफ पूरी उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। अदालत को मामले में आरोपी की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की मदद से फंसाया गया है, अदालत को और भी अधिक सावधानी और सावधानी के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि मामलों में अति-प्रभाव सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है।

(ज) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाना चाहिए, और आरोपी के उत्पीड़न, अपमान और अन्यायपूर्ण हिरासत की रोकथाम होनी चाहिए।

(झ) न्यायालय को गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका पर विचार करना चाहिए।

(ञ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह

होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

24. इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो पहले ही ऊपर उजागर किए जा चुके हैं, हम महसूस करते हैं कि 17 साल पुरानी कथित घटना के संबंध में अग्रिम जमानत से इनकार करके, एक विचाराधीन के रूप में, अपीलार्थी को सलाखों के पीछे जाने के लिए मजबूर करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और जिसके लिए आरोप केवल वर्ष 2014 में तैयार किया गया है। जाँच पूरी हो चुकी है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी न्याय के मार्ग से भाग सकता है। एफ. आई. आर. दर्ज की गई और मुकदमा वर्ष 2001 में शुरू हुआ; यद्यपि आई. पी. सी. की धारा 506 (2) के तहत बनाए गए आरोप के साथ, और इन सभी अवधियों के दौरान, अपीलार्थी ने कार्यवाही में भाग लिया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस अवधि के दौरान उसने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, भले ही अपीलार्थी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाया गया हो, जब ऊपर बताए गए अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जाती है तो यह अपने आप में अग्रिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं होना चाहिए।

25. अभियोजक ने इन कार्यवाहियों में नए साक्ष्य का अध्ययन करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसके आधार पर वह दावा करती है

कि अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत और नियमित जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। हमारे लिए इस आवेदन में लगाए गए आरोपों में जाना आवश्यक नहीं है। वह जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत के समक्ष इस तरह का आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने इस आवेदन के गुण-दोषों का अध्ययन नहीं किया है और जब भी ऐसा आवेदन किया जाएगा, निचली अदालत उसी की जांच करने और आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी जो निचली अदालत कानून के अनुसार उचित समझे।

26. अलग होने से पहले, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, हमारा विचार है कि इस मामले में मुकदमा तेजी से चलाया जा सकता है और निचली अदालत को एक साल के भीतर इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

27. नतीजतन, हम विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं और उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देने वाले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांकित आदेश को बहाल करते हैं। उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

अपीलों की अनुमति दी गई ।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।